नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

फर्जी पासपोर्ट कांड में घिरी पुलिस

गलत पते को सही बताने वाले पुलिसकर्मियों पर अब तक न एफआइआर, न विभागीय कार्रवाई

विशेष प्रतिनिधि

भोपाल, 23 अक्टूबर . बांग्लादेशियों के फर्जी पासपोर्ट मामले में पासपोर्ट बनवाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन फर्जी पते का सत्यापन कर उसे सही बताने वाले पुलिसकर्मियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि, फर्जीवाड़ा उजागर होने के करीब दो माह बीत चुके हैं.

इस मामले में हाईकोर्ट ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि जब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाना अपराध है, तो उस फर्जी पते को सही बताने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही. मालूम हो कि एसटीएफ की पूछताछ के दौरान मास्टरमाइंड रियाल चौधरी से पुलिसकर्मियों की भूमिका से जुड़ी जानकारी का खुलासा भी हो चुका है. एसटीएफ ने संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर जांच करने को कहा है. स्पेशल टास्क फोर्स भोपाल, ग्वालियर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पासपोर्ट की जांच कर रही है. अब तक सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. 10 नए संदिग्धों की जानकारी भी मिली है. 19 फरार आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.

40 पासपोर्ट भोपाल के मठ के पते पर बने

एसटीएफ की अब तक की जांच में सामने आया कि 40 पासपोर्ट भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के अन्ना नगर स्थित बौद्ध मठ के पते पर तैयार कराए गए. अधिकतर पासपोर्ट कोरोना काल के दौरान बनाए गए. वेरीफिकेशन करने वाले अधिकतर पुलिसकर्मी दूसरे थानों पर पदस्थ हो चुके हैं. उन पर अब तक कार्रवाही नहीं हुई. थाना प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध मिली है. बावजूद अब तक कार्रवाही नहीं हुई. सभी पासपोर्ट मास्टर माइंड रियाल चौधरी के कहने पर बनाए गए. रियाल भोपाल जेल में बंद है.

अफसर की भूमिका संदिग्ध

जांच एजेंसी को भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में पदस्थ रह चुके एक अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध मिली है. संबंधित अधिकारी का भोपाल से तबादला हो चुका है. एसटीएफ विदेश मंत्रालय और पासपोर्ट सेल से उन संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है, जो इन पासपोर्ट के जरिए विदेश गए और वापस नहीं लौटे. अब तक ऐसे पांच नाम सामने आने की बात कही गई है.

एक्सपर्ट व्यू

पुलिसकर्मी ने जानबूझकर फर्जी पते को सही प्रमाणित किया है तो उसकी भूमिका भी गंभीर है. साक्ष्यों के आधार पर उसे सहआरोपी बनाने पर विचार किया जाना चाहिए. पुलिस कर्मी की आपराधिक जिम्मेदारी उसकी भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों से ही तय होगी. एसटीएफ को ही पुलिस की भूमिका की जांच कर आगे की कार्रवाही करना सही रहेगा.

जगदीश गुप्ता, अधिवक्ता

जांच के लिए संबंधित एसपी को पत्र लिखा

फर्जी पते का सत्यापन करने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच के लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है. आगे की कार्रवाई पुलिस अधीक्षकों को करनी है. एसटीएफ अभी मामले की जांच कर रही है.

-राजेश भदौरिया, एआईजी, एसटीएफ

पेपरलेस होगा विस का बजट सत्र

ई-विधान व्यवस्था बजट सत्र से पूरी तरह लागू करने की तैयारी

कन्हैया लोधी

भोपाल, 23 अक्टूबर. मध्यप्रदेश विधानसभा में दो साल से अटकी ई-विधान व्यवस्था अब अगले बजट सत्र से पूरी तरह लागू करने की तैयारी है. ऐसा हुआ तो फरवरी-मार्च 2027 में होने वाला बजट सत्र पेपरलेस होगा. इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की कवायद शुरू कर दी है.

विधानसभा सचिवालय की ओर से 28 से 30 अक्टूबर तक विधायकों और उनके निज सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. विधानसभा परिसर स्थित लोक सेवा केंद्र विधान परिषद में होने वाले इस प्रशिक्षण के लिए विधायकों के बैच बनाए गए हैं.

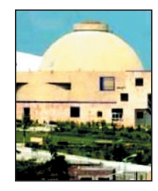

विधायकों को 28 से ट्रेनिंग का सिलसिला होगा शुरू

28 और 29 अक्टूबर को 50-50 के दो बैच में प्रतिदिन 100 विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 30 अक्टूबर को 30 विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी. सचिवालय ने सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना दे दी है. इससे पहले भी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

टैबलेट पर मिलेंगे सवाल-जवाब और विधेयक: नेशनल ई-विधान परियोजना के तहत नेवा एप्लीकेशन के मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया जाएगा. व्यवस्था लागू होने पर विधायकों के प्रश्न, उत्तर, विधेयक, ध्यानाकर्षण सूचनाएं और अन्य सदन संबंधी सामग्री डिजिटल उपलब्ध होगी. विधायक कहीं से भी लॉगिन कर सामग्री देख सकेंगे. विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए जा चुके हैं और पिछले बजट सत्र में बजट भी डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया गया था.

कई राज्य लागू कर चुके हैं व्यवस्था

ई-विधान परियोजना के लिए केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी खर्च वहन करती है. इसके बावजूद मध्यप्रदेश में व्यवस्था अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है. गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु और असम समेत कई राज्य इसे लागू कर चुके हैं.

एक नजर में

लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र हटाओ अभियान आज से

भोपाल. कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर सहित अन्य विषयों को लेकर फैलाए जा रहे झूठ को बेनकाब करने के लिए भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र बचाओ अभियान शनिवार 24 अक्टूबर से शुरू होगा. 5 नवंबर तक चलने वाले अभियान के लिए भाजपा ने बूथ स्तर तक तैयारी की है. भाजपा ने जो तैयारी की है उसके हिसाब से अभियान के तहत जिला और विधानसभा स्तर पर लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र हटाओ पदयात्रा निकाली जाएगी. इसके साथ ही राष्ट्र चिंतन संवाद कार्यक्रम के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद किया जाएगा.

इंदौर के व्यापारी से 40 लाख की ठगी

रतलाम. रतलाम में नकली सोने-चांदी के आभूषणों को असली बताकर ठगी करने की कोशिश में पकड़ाए गिरोह ने इंदौर के एक व्यापारी से 40 लाख रुपये की ठगी की है. पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी मानसिंह ने इंदौर के व्यापारी से 40 लाख रुपये की ठगी करने की बात कबूल की है. इस वारदात की रिपोर्ट इंदौर के लसुड़िया थाने में पहले से दर्ज है. रतलाम पुलिस ने 18 अक्टूबर को रतलाम में एक बर्तन व्यवसायी को ठगने की कोशिश में 6 आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं.

ग्वालियर हादस में मृतकों के परिजन को नौकरी

ग्वालियर. नगर निगम परिषद में शीतला माता मंदिर हादसे में 16 लोगों की मौत के मामले में शोक प्रस्ताव पर चर्चा हुई. हर मृतक के परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर नौकरी दी जाएगी. घायलों की भी मदद की जाएगी. प्रस्ताव पर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एकमत रहे. महापौर डॉ. शोभा सिकरवार ने हादसे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि जब मंदिर तक दोपहिया और चारपहिया वाहन नहीं जा सकते थे, तो ट्रक कैसे पहुंच गया?

2.75 करोड़ की फर्जी एफडीआर से शराब ठेका

दो साल बाद खुला मामला

बैंक ने दस्तावेजों को अपना मानने से किया इनकार

विशेष प्रतिनिधि

भोपाल, 23 अक्टूबर . राजधानी में शराब दुकान का ठेका हासिल करने के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक की फर्जी एफडीआर जमा करने का मामला सामने आया है. पीएंडटी चौराहा मदिरा दुकान समूह के ठेकेदार जसवंत पर फर्जी बैंक दस्तावेज और सत्यापन रिपोर्ट जमा करने का आरोप है.

कोहेफिजा पुलिस ने धोखाधड़ी और कूटरचना से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है. मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. आबकारी विभाग के पत्र के मुताबिक, वर्ष 2024-25 के लिए पीएंडटी चौराहा मदिरा दुकान समूह 23 फरवरी 2024 को लॉटरी के जरिए हरियाणा के झज्जर निवासी जसवंत को आवंटित किया गया था. समूह का वार्षिक मूल्य 27 करोड़ 55 लाख 35 हजार 348 रुपये था. नियमों के तहत ठेकेदार को इसकी 10 प्रतिशत राशि, यानी 2 करोड़ 75 लाख 53 हजार 535 रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करनी थी.

जांच में सामने आया कि जसवंत ने इस राशि की प्रतिभूति के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ई-एफडीआर आबकारी कार्यालय में जमा की. इतना ही नहीं 20 मई 2024 को अपने ई-मेल से एफडीआर के सत्यापन संबंधी बैंक का पत्र भी भेजा. मामले में सबसे अहम खुलासा तब हुआ जब आबकारी विभाग ने अक्टूबर 2026 में बैंक से एफडीआर और सत्यापन रिपोर्ट की दोबारा जांच कराई.

डिप्टी सीएम के ओएसडी पर लग चुके आरोप

दीपम रायचुरा

अभी पुलिस ने सिर्फ जसवंत को आरोपी बनाया है. अब पुलिस यह पता लगा रही कि फर्जी एफडीआर और सत्यापन रिपोर्ट किसने तैयार की, इन्हें तैयार करने में आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका थी या नहीं और विभाग में जमा दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई. बतादें, भोपाल के तत्कालीन प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा पर करीब 2.75 करोड़ रुपये की फर्जी इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (ई-एफडीआर) स्वीकार कर शराब दुकानों का ठेका जसवंत को दिलाने में सहयोग करने का आरोप है. आरोपों के बाद उन्हें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ओएसडी पद से हटा दिया था.

20 हजार रिश्वत लेते निगम क्लर्क गिरफ्तार

जबलपुर. ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण कार्य के लिए बैंक लोन की एनओसी जारी करने के एवज में कटनी नगर निगम के लिपिक को लोकायुक्त टीम ने शुक्रवार को 20 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग के रूप में हुई है. एसपी ने बताया कि ट्रांसपोर्टर अशोक कनकने को प्लॉट पर निर्माण कार्य कराने के लिए उन्होंने बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन किया था. बैंक प्रबंधन ने ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया के तहत नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा था.

पंचायत मंत्री ने दिए अप्रैल-मई में चुनाव के संकेत

नवभारत न्यूज

भोपाल, 23 अक्टूबर . मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं. डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश की करीब 23 हजार पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से एक-दो महीने पहले चुनाव कराने की तैयारी कर रही है. चुनाव से पहले पंचायत राज व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी भी है.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ग्राम सभा के अधिकार पंचायत समितियों को दिए जाएंगे. सरकार नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है. इसके अलावा पंचायतों को नगरपालिका की तरह टैक्स लगाने का अधिकार देने की दिशा में भी काम हो रहा है. सरकार नवंबर तक यह बदलाव लागू करना चाहती है. ग्राम सभा गांव के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के साथ कई फैसलों में अहम भूमिका निभाती है. ऐसे में उसके अधिकार पंचायत समितियों को देने का प्रस्ताव पंचायत राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा. सरकार पंचायतों को नगरपालिका की तरह टैक्स लगाने का अधिकार देने की दिशा में काम कर रही है. हालांकि, पंचायतें किन मदों में टैक्स वसूल सकेंगी और इसकी दरें क्या होंगी, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

एक -दो महीने में कार्यकाल पूरा करने की तैयारी

बालाघाट सम्मेलन में बोले एक माह में नोटिफिकेशन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बालाघाट जिले के वारासिवनी जनपद की ग्राम पंचायत गर्रा में सरपंच सम्मेलन के दौरान ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव कार्यकाल पूरा होने से एक या दो महीने पहले कराए जाएंगे, ताकि नई पंचायतों को समय पर कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया पूरी हो सके. मंत्री के मुताबिक, चुनाव से पहले पंचायत राज नियमों में बदलाव किया जाएगा. इसके लिए एक महीने में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है. पंचायत राज नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है.

इंदौर से बैंकॉक अब मिलेगी सीधी उड़ान

2 दिसंबर से शुरू होगी सेवा

इंदौर, 23 अक्टूबर . इंदौर से थाईलैंड जाने वाले यात्रियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. एयर इंडिया एक्सप्रेस इंदौर और बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है.

डीजीसीए द्वारा जारी फाइनल विंटर शेड्यूल में इस उड़ान की शुरुआत 2 दिसंबर से तय कर दी गई है. इससे इंदौर की अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और थाईलैंड यात्रियों को सुविधा होगी. अब एयरलाइन की आधिकारिक बुकिंग शुरू होने का इंतजार है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के फाइनल विंटर शेड्यूल के अनुसार इंदौर और बैंकॉक के बीच विमान सप्ताह में चार दिन- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार—संचालित होगा. यह उड़ान 26 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है. इस रूट पर बोइंग 737 मैक्स 8 विमान का उपयोग होगा, जिसमें एक बार में लगभग 176 यात्रियों के बैठने की क्षमता है.

फाइनल शेड्यूल में मिली आधिकारिक जगह

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विंटर शेड्यूल में इस उड़ान के लिए विशेष स्लॉट मांगा था. शुरुआत में संभावित तारीख 1 नवंबर बताई जा रही थी, लेकिन फाइनल शेड्यूल में इसे 2 दिसंबर से मंजूरी दी गई है. कंपनी ने अभी आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग शुरू नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द बुकिंग शुरू होगी. ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अमोल कटारिया ने बताया कि फिलहाल इंदौर से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है, जिससे यात्रियों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है.

सागर में अवैध पटाखों के भंडारण पर बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सागर, 23 अक्टूबर. दीपावली से पहले अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

मोतीनगर थाना क्षेत्र में बालाजी मंदिर रोड के पास एक मकान से करीब 8 से 10 लाख रुपये कीमत के पटाखे जब्त किए गए हैं. मौके से लगभग 25 पेटी पटाखे मिले. मकान मालिक सुनील शर्मा पटाखों के भंडारण से संबंधित लाइसेंस पेश नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने पूरा भंडार जब्त कर लिया. गुरुवार देर रात मोतीनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालाजी मंदिर रोड के पास सुनील शर्मा के मकान में बड़ी मात्रा में अवैध आतिशबाजी का भंडारण किया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

मकान से 10 लाख के पटाखे किए जब्त

स्टॉक मार्केट के नाम पर 8.59 लाख की ठगी

इंदौर. फेसबुक पर शेयर मार्केट का विज्ञापन देखकर वॉटर पार्क संचालक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए. आरोपियों ने पहले 10-20% मुनाफा दिखाया, फिर ट्रेडिंग के नाम पर ?8.59 लाख जमा कराए और खाते में ?29 लाख का फर्जी मुनाफा दिखाया. आईपीओ में शेयर दिलाने के नाम पर ?18 लाख और मांगे गए. हीरानगर पुलिस ने रितेश कुमार निमाड़े की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हवलदार के पास 20 करोड़ की बेनामी संपत्ति

- मां के नाम पर खरीदी छह लाख की आरा मशीन
- दो भूखंडों की बाजार कीमत 60 लाख रुपए से ज्यादा

नवभारत न्यूज

इंदौर, 23 अक्टूबर . पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर लोकायुक्त की सर्च कार्रवाई में अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति का पता चला है. जांच में 50 अचल संपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी गाइडलाइन कीमत 18.29 करोड़ रुपए और वर्तमान बाजार कीमत करीब 65.71 करोड़ रुपए आंकी गई है.

50 अचल संपत्तियां सामने आई

लोकायुक्त ने 14 अक्टूबर को फिरोज खान के विभिन्न आवासों और अन्य ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की थी. इसके बाद जांच में देवास के सीनियर राधागंज क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में दो भूखंडों की जानकारी सामने आई. ये भूखंड साहिल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से खरीदे गए थे. 958 वर्गफीट के एक भूखंड की खरीद कीमत 8.74 लाख रुपए और 1060 वर्गफीट के दूसरे भूखंड की कीमत 9.32 लाख रुपए दर्ज है. दोनों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 60.54 लाख रुपए आंकी गई है. जांच में महाराजा रियल एस्टेट के बैंक खाते में 9.70 लाख रुपए जमा होने की जानकारी भी मिली है. अब तक बैंक खातों में कुल 19.76 लाख रुपए जमा पाए हैं. लोकायुक्त की अब तक की जांच में 20,00,36,570 रुपए की चल-अचल संपत्ति सामने आई है. इसमें शामिल 50 अचल संपत्तियों की बाजार कीमत 65,71, 90,768 रुपए है.

प्रभारी प्राचार्य सहित पांच शिक्षकों की रुकी वेतनवृद्धि

जबलपुर. विकासखंड कुंडम स्थित शासकीय हाईस्कूल तिलसानी में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति और गिरते शैक्षणिक स्तर पर प्रभारी प्राचार्य सहित पांच शिक्षकों के विरुद्ध संयुक्त संचालक लोक शिक्षण घनश्याम सोनी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री जनविश्वास कार्यक्रम के अंतर्गत 9 अक्टूबर 2026 को किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय में व्यापक खामियां पाई गई थीं. निरीक्षण में विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम तथा शैक्षणिक स्तर असंतोषजनक था.

स्वाभिमान यात्रा | निष्पक्ष चुनाव को लेकर सरकार की मंशा पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा समर्थन

यात्रा के साथ वोट चोरी-चंदा चोरी पर लोगों से सीधा संवाद

विशेष संवाददाता

उज्जैन, 23 अक्टूबर. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुक्रवार को चौथे दिन तराना से आगे बढ़ी. उज्जैन से अयोध्या तक निकाली जा रही इस पदयात्रा को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है.

यात्रा शुक्रवार सुबह तराना स्थित आईटीआई कॉलेज, सिद्धपुर रोड से प्रारंभ हुई. दिग्विजय सिंह संतों, साधु-संतों और समर्थकों के साथ सिद्धपुर तथा निपानिया पहुंचे. दोपहर में भोजन और विश्राम के बाद यात्रा शंकरपुर चौराहे से पुनः रवाना हुई. इसके बाद कनार्दी, गुठलाई चौराहा और देवखेड़ा होते हुए जुनापानी चौराहे तक पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित था.

यात्रा में दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय भी शामिल हैं. शुक्रवार को उन्होंने खेतों में प्याज की रोपाई कर रही महिला किसानों से मुलाकात कर उनकी कृषि संबंधी समस्याएं और अनुभव जाने. इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ प्याज के पौधे लगाए और फसलों में पानी भी दिया. लगभग 930 किलोमीटर लंबी यह यात्रा उज्जैन से शुरू हुई है और ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी.

यात्रा का उद्देश्य धार्मिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के मुद्दों को उठाना है.

ईवीएम के बजाय मतपत्रों से हो चुनाव

ग्रामीणों से संवाद के दौरान दिग्विजय सिंह ने धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, सनातन परंपराओं के सम्मान और मतदान के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया. उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई. साथ ही, कथित वोट चोरी पर सवाल उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग की.